


कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला

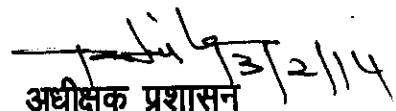
आदेश क्रमांक 10/9-2012 प्रशा0 (4)

दिनांक, पंचकूला 13/2/14

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक 22/22/2004-3 जी0एस0111 दिनांक 06.01.2014, अन्य पिछड़े वर्गों (ओ0बी0सी0) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन पत्र निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुडगांव।
3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
4. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
5. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
6. मुख्यालय के सभी अधिकारी/अधीक्षक।
7. निजी सचिव/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
8. जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-1 एवं 11
9. प्रौद्योगिकी अधिकारी (आई0टी0सैल) मुख्यालय।


6/3/14
Programmer.


अधीक्षक प्रशासन
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला
8

DSE

80Admn(G)
29-114

कमांक 22/22/2004-3जी.एस.।।।

51858-C.S.—H.G.P.—Chd.

प्रेषक

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष ।
2. रोहतक, गुड़गांव, हिसार एवं अम्बाला मण्डलों के आयुक्त ।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
4. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।
5. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड / निगमों एवं सार्वजनिक उपकरणों के अध्यक्ष / प्रबन्धक निदेशक ।

रजिस्ट्रार महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, करुक्षेत्र, विश्वविद्यालय, करुक्षेत्र, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार तथा चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 06.01.2014

विषय:

अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों / वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिये आय के मानदण्डों में संशोधन ।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान सरकार के पत्र कमांक 22/22/2004-3जी.एस.।।। दिनांक 22.01.2009 की ओर दिलाऊँ जिस द्वारा यह सूचित किया गया था कि भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग) द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्गों को केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में दाखिले हेतु आय सीमा 4.5 लाख रू० प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी ।

अब भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पत्र कमांक 11-13/2012-यू० पॉलिसी, दिनांक 31.5.2013 (प्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया है कि अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्गों को केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में दाखिले हेतु आय सीमा 4.5 लाख रू० प्रति वर्ष से बढ़ाकर 6.0 लाख रू० प्रतिवर्ष कर दी है तदानुसार आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार की उपरोक्त अंकित हिदायतें दिनांक 31.05.2013 की अनुपालना दृढ़ता से की जाए ।

भवदीय

शुभाजि आर्य

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ० क्रमांक 22/22/2004-3जी.एस.॥

दिनांक 06.01.2014

इसकी एक-एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, चण्डीगढ़ ।
2. सचिव, हरियाणा कर्मचारी सेवा आयोग, चण्डीगढ़ ।

सुभाष आर्य

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

H

इसकी एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों एवं प्रधान सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

सुभाष आर्य

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

H

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा: क्रमांक 22/22/2004-3जी.एस.॥

दिनांक 06.01.2014

इसकी एक-एक प्रति मुख्य मंत्री के प्रधान सचिवों/अतिरिक्त प्रधान सचिव/उप-प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान विशेष कार्याधिकारी तथा विशेष कार्याधिकारी /मंत्रियों /राज्य मंत्रियों एवं मुख्य संसदीय सचिवों के सचिव/ निजि सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित है ।

सुभाष आर्य

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

H

सेवा में

मुख्य मंत्री के प्रधान सचिवों/ अतिरिक्त प्रधान सचिव / उप-प्रधान सचिव /
मुख्य मंत्री के प्रधान विशेष कार्याधिकारी तथा विशेष कार्याधिकारी, मंत्रियों /राज्य
मंत्रियों एवं मुख्य संसदीय सचिवों के सचिव/ निजि सचिव ।

अशा: क्रमांक 22/22/2004-3जी.एस.॥

दिनांक 06.01.2014

पृ० क्रमांक 22/22/2004-3जी.एस.॥

दिनांक 06.01.2014

इसकी एक प्रति सदस्य सचिव, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

सुभाष आर्य

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

H

पृ० क्रमांक 22/22/2004-3जी.एस.॥

दिनांक 06.01.2014

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय हरियाणा (उनसे अनुरोध है कि इन हिदायतों को राज्य के सभी नगरपालिकाओं / निगमों तथा परिषदों को भेज दी जाये) ।
2. निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा को इन हिदायतों को पर्याप्त प्रचार हेतु ।

सुभाष अग्रवाल

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति, हरियाणा सिविल सचिवालय / वितायुक्त राजस्व विभाग के सभी अधीक्षकों / उपाधीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

सुभाष अग्रवाल

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी अधीक्षक / उपाधीक्षक, हरियाणा सिविल सचिवालय
तथा वितायुक्त राजस्व विभाग ।

अशा: क्रमांक 22/22/2004-3जी.एस.॥
पृ० क्रमांक 22/22/2004-3जी.एस.॥

दिनांक 06.01.2014
दिनांक 06.01.2014

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. प्रिंसिपल,
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 39-40 बेज, काडा भवन,
सैक्टर-4, पंचकुला ।
2. प्रिंसिपल मण्डलीय,
प्रशिक्षण केन्द्र, एस.सी.ओ. न० 11,
सैक्टर-16,
पंचकुला ।

सुभाष अग्रवाल

अवर सचिव सामान्य सेवायें
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

3

No. 36033/1/2013-Estt. (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

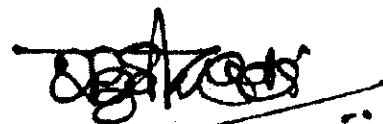
North Block, New Delhi,
Dated: the 27th May, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs)-reg.

The undersigned is directed to invite attention to this Department's office memorandum No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8th September, 1993 which, *inter-alia*, provided that sons and daughters of persons having gross annual income of Rs. 1 lakh or above for a period of three consecutive years would fall within the creamy layer and would not be entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes. The aforesaid limit of income for determining the creamy layer status was subsequently raised to Rs. 2.5 lakh and Rs. 4.5 lakh and accordingly the expression "Rs. 1 lakh" under Category-VI of Schedule to OM dated 8th September, 1993 was revised to "Rs. 2.5 lakh" and to "Rs. 4.5 lakh" vide this Department's OMs No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 09.03.2004 and dated 14.10.2008 respectively.

2. It has now been decided to raise the income limit from Rs. 4.5 lakh to Rs. 6 lakh per annum for determining the creamy layer amongst the Other Backward Classes. Accordingly, the expression "Rs. 4.5 lakh" under Category VI in the Schedule to this Department's aforesaid O.M. of 8th September, 1993 would be substituted by Rs. "Rs. 6 lakh".
3. The provisions of this office memorandum have effect from 16th May, 2013.
4. All the Ministries/Departments are requested to bring the contents of this office memorandum to the notice of all concerned.



(Sharad Kumar Srivastava)

Under Secretary to the Govt. of India

To:

1. All the Ministries/Departments of the Government of India.

Contd. 2....

2. Department of Financial Services, New Delhi.
3. Department of Public Enterprises, New Delhi.
4. Railway Board, New Delhi.
5. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission of India/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission.
6. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
7. Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi
8. National Commission for SCs/National Commission for STs, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
9. National Commission for Backward Classes, Trikot-1, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi.
10. Office of the Comptroller and Auditor General of India, 10 Bahadur Shah Jafar Marg, New Delhi-110002.
11. Information and Facilitation Centre, DoPT, North Block, New Delhi (100 copies).
- ✓ 12. The NIC, DoPT with a request to upload it at the website of this Department in OMs & Orders > Estt. (Res.) > SC/ST/OBC and in 'What's New'

Copies forwarded to:

The Chief Secretaries of all the States/Union Territories for information and necessary action.

Annexure

No. 11-13/2012-U.Policy
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 31st May, 2013.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/ section (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs) in admissions to Central Educational Institutions

- Ref: 1) OM No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dt. 8/9/1993 of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training (DoPT))
2.) OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dt. 9/3/2004 of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, DoPT
3) OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dt. 14/10/2008 of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, DoPT
4) OM No. 1-1/2008-U1A dt. 13/10/2008 of Ministry of Human Resource Development.

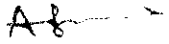
Attention is invited to O.M.No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8th September, 1993 of DoPT which, *inter-alia*, provided that sons and daughters of persons having gross annual income of Rs.1 lakh or above for a period of three consecutive years would fall within the creamy layer and would not be entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes. The aforesaid limit of income for determining the creamy layer status was subsequently raised to Rs.2.5 lakh and Rs.4.5 lakh and accordingly the expression "Rs 1 lakh" under Category-VI of Schedule to OM dated 8th September, 1993 was revised to "Rs.2.5 lakh" and to "Rs.4.5 lakh" vide DoPT's O.M. No.36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 09.03.2004 and dated 14.10.2008 respectively. Vide O.M.No. 1-1/2008-U1A dt. 13/10/2008 of Ministry of Human Resource Development, the Central Government specified that as per the above-mentioned DoPT O.M. dated 14.10.2008, the income limit for determining the "creamy layer" among OBCs shall be Rs.4.5 lakhs for reservation in admissions to Central Educational Institutions.

2. The DoPT, vide OM No. 36033/1/2013-Estt. (Res.) dt. 27th May, 2013 has now notified that the limit of income for determining 'creamy layer' status amongst the OBCs is raised from Rs. 4.5 lakhs to Rs. 6 lakhs per annum with effect from 16th May, 2013 and that the expression "Rs. 4.5 lakh" under Category VI in the Schedule to OM No. 36012/22/93-Estt. (SCT) of 8th September, 1993 of Ministry of Personnel,

Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) is substituted by "Rs. 6 lakh".

3. Accordingly, with the approval of the competent authority, the revised expression of "Rs. 6 lakh" under Category VI in the Schedule to the OM dt. 8/9/1993 of DoPT shall be the limit of income, with effect from 16th May, 2013, for determining 'creamy layer' status amongst the OBCs for reservation in admissions to Central Educational Institutions.

4. The provisions of this OM are in supersession of this Department's OM No. 1-1/2008-U1(A) dt. 13/10/2008.


(Amit Shukla)

Deputy Secretary to the Government of India

To

- 1) All Central Educational Institutions
- 2) All the Ministries/ Departments of Government of India.
- 3) Chief Secretaries of all States
- 4) Administrators of UTs
- 5) National Commission for Backward Classes.
- 6) All Regulatory Councils responsible for maintenance/ determination of standards of higher education
- 7) Webmaster (NIC), MHRD for uploading of the same on MHRD's website.